भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1313
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024/ 12 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सड़कों की स्थिति

†**1313. श्री बिष्णु पद राय:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिसम्बर, 2018 में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के अपने दौरे के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पारित निदेश के संदर्भ में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सड़कों की स्थिति के चिन्हिकरण हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया था;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण पर कितनी लागत आई तथा इस सर्वेक्षण पर कितना व्यय किया गया;
(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक कितनी निधि आवंटित की गई है;
(घ) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सड़कों की मरम्मत/नवीकरण करने और नई सड़कें बिछाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण किया गया और निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद को 1.15 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) -II और विशेष वित्तीय सहायता (एसएफए) योजनाओं के अंतर्गत सड़कों के सर्वेक्षण के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। पीएमजीएसवाई और एसएफए योजनाओं के अंतर्गत कुल 198 सड़कों के निर्माण के लिए 210.87 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसमें से 100 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सुधार के लिए 142 सड़कों तथा निर्माण के लिए 8 नई सड़कों की पहचान की है।

(ङ) पिछले पांच (5) वर्षों के दौरान पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा निर्मित नई बिटुमिनस ग्रामीण सड़कों की कुल संख्या 128 है, जिनकी कुल लंबाई 36.44 किमी है।

****